भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 47*

जिसका उत्तर मंगलवार 06 जनवरी, 2018 को दिया जाना है

फेम इंडिया स्कीम

47*. डॉ के गोपाल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई "फास्टर एडॉप्सन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया" (फेम इंडिया) का प्रायोगिक चरण अथवा प्रथम चरण को 31 मार्च, 2018 तक के लिए बढ़ाया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार फेम इंडिया स्कीम का चरण-II शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन पर आधरित मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट को शुरू करने की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (घ): एक विवरण सदन-पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'फेम इंडिया स्कीम' के संबंध में डॉ के. गोपाल द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2018 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 47 के भाग (क)से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से दो वर्षों की आरंभिक अवधि (चरण-I) के लिए नामतः फेम इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण] योजना तैयार की। फेम इंडिया योजना की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के चरण-I में प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर उचित रूप से समीक्षा की जाएगी। तथापि, फेम इंडिया योजना का चरण-I, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर आरंभ में दो वर्षों की अवधि के लिए था, को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।

भारी उद्योग विभाग को इस योजना के लिए अगले कदमों की तैयारी करनी है।

(ग) और (घ): सार्वजनिक परिवहन में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन पर आधारित सार्वजनिक और साझा मोबिलिटी के लिए मांग प्रोत्साहनों को बढ़ाने हेतु दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों और विशेष श्रेणी के राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए दिनांक 31 अक्तूबर, 2017 को एक रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई। इस प्रतिक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार से ₹4054.60 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता लेते हुए 3144 ई-बसों, 2430 ई-फोर व्हीलर टेक्सियों और 21545 ई- थ्री व्हीलर ऑटो की कुल आवश्यकता के साथ 21 राज्यों के 44 शहरों से 47 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों की जांच करने के बाद चयन मानदंड के आधार पर निधियन हेतु निम्नलिखित ग्यारह (11) शहरों का चयन किया गया:-

क्रम संख्या	**शहर**	**बस**	**चोपहिया**	**तिपहिया**
1.	दिल्ली	40	-	-
2.	अहमदाबाद	40	20	20
3.	बेंगलुरू	40	100	500
4.	जयपुर	40	-	-
5.	मुंबई	40	-	-
6.	लखनऊ	40	-	-
7.	हैदराबाद	40	-	-
8.	इंदौर	40	50	200
9.	कोलकाता	40	200	-
विशेष श्रेणी के राज्यों के शहर				
10.	जम्मू	15	-	-
11.	गुवाहाटी	15	-	-
	कुल	**390**	**370**	**720**

चुने गए शहरों को निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देना और दिनांक 28 फरवरी, 2018 से पहले आपूर्ति आदेश जारी करना अपेक्षित है। इस रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से भारी उद्योग विभाग द्वारा फेम इंडिया योजना (चरण-I) के तहत लगभग ₹437 करोड़ खर्च किए जाने की संभावना है, जिसमें चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु प्रोत्साहनों के रूप में लगभग ₹40 करोड़ शामिल हैं।

*****